समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

RNI No. MPHIN/2001/11140

वर्षः– 2019–20 पृष्ठः– 4 अंक :– 51 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

बढ़ती आबादी के बढ़ते संकट – डॉ. किशन कछवाहा

बढ़ती आबादी का संकट दिन प्रतिदिन गम्भीर होता चला जा रहा है लेकिन देश के राजनीतिक दल इस पर चर्चा करने से बचते नजर आ रहे हैं। इस समय देश की आबादी एक अरब पैंतीस करोड़ को भी पार कर चुकी है। इनमें साढ़े ग्यारह करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों सहित बांग्लादेशी घुसपैठिये भी शामिल है। यह घुसपैठियों की समस्या बेहद चिन्ताजनक बन गयी है। इस निरन्तर विस्तार ले रही आबादी के लिये खाद्य सामग्री, पेयजल आदि के साथ–साथ सुरक्षा सम्बंधी अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान समय में जो वैश्विक भूख सूचकांक की सूची सामने आयी है, उसके अनुसार भारत का निम्न श्रेणी में दिखना अत्यन्त चिन्ता का विषय होना चाहिये। अब समय आ गया है, जब नीति निर्माताओं और कृषि वैज्ञानिकों को इस गम्भीर चुनौती को लेकर आत्म चिन्तन करना चाहिए। देश में वैसे ही खाद्य व पोषण के साधन कम होते जा रहे हैं। इनकी वृद्धि पर विचार करते हुये इनकी सुरक्षा के मामले में अन्यान्य तरीके ईजाद करने की जरूरत है।

ऐसे अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रीय मुद्दे जनसंख्या के मामले में देश के किसी हिस्से में भी चर्चा की शुरूआत न होना एक गम्भीर सवाल तो पैदा करता ही है। आखिर देश के राजनैतिक दल इस प्रकार की चर्चा करने से आखिर बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? संसद में भी इस तरह की चर्चा अब तक सुनने में नहीं आ सकी है जबकि आबादी के बढ़ने से तरह–तरह की समस्याओं और यातायात जैसी समस्याओं से लोगों को रोज जूझना पड़ रहा है। बड़े छोटे शहरों में जाम की समस्या से घण्टों फंसे रहने के कारण समय और ईंधन का दुरूपयोग हो रहा है।

बढ़ती आबादी की समस्या और कृषि उत्पादन बढ़ाना एक दूसरे से जुड़े मामले हैं। इस मामले में यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम भयंकर भी हो सकते हैं। वर्तमान में देश का खाद्यान्न उत्पादन 2833.7 लाख टन है। यह अच्छी स्थिति तो है लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से इसे और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का क्रम 102वें स्थान पर प्रदर्शित होना इस चिन्ता में बढ़ोत्तरी ही कर रहा है।

संतोष की बात यह है कि देश का कुल उत्पादन सन् 1950–51 की तुलना में 570 लाख टन की तुलना में 2833.7 लाख टन पर पहुंच गया है। इसी प्रकार चांवल और गेहूँ का उत्पादन कृषि वर्ष 2018–19 में एक हजार लाख टन से भी अधिक रहा है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता तो हासिल कर ली है लेकिन महज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक देश के लिये पर्याप्त नहीं होती। इसके साथ–साथ बढ़ती आबादी के लिये अन्य बहुत सी चीजों की जरूरत भी महसूस होती है, जिनके बारे में विशेषज्ञों को चिन्तन करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को खाद्यान्न के साथ–साथ पर्याप्त विटामिन भी मिल सके ताकि वह बीमारियों की चपेट में आने से बचाव कर सके। अतः पोषण की परेशानियों से बचाव के तरीके हमारे प्रयासों में शामिल हों।

हमारे देश के राजनीतिक दल बड़ी चतुराई के साथ बढ़ती मंहगाई की बात तो बड़े जोर–शोर से कहने में कभी नहीं चूकते लेकिन वर्तमान संशाधनों का षाड़यांत्रिक तरीकों से अवैधानिक ढंग से घुस आये घुसपैठियों के द्वारा किये जा रहे दुरूपयोग के बारे में बोलते हुये लजाते हैं। ये तत्व विद्यमान आबादी के संशाधनों का ही तो उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं देश में जहां–जहां बसे हैं वहाँ अपराध की दुनिया बसाये हुये हैं, नशा का बाजार खोले हैं और तो ओर ये देश की सुरक्षा के लिये भी खतरा बने हुये– शांति और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इन्हें किन कारणों से सहन किया जा रहा है? यह बात समझ से परे है। इन्हें क्यों वोट बैंक के चश्मे से देखा जाकर नजर अन्दाज किया जा रहा है।

देश में निरन्तर बढ़ती आबादी के कारण भोजन सामग्री, तेल, गैस नित्य उपयोग में आने वाली चीजों की कमी पड़ेगी तो उनका दाम बढ़ना स्वाभाविक है। पड़ोसी पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है–वह भी देखने और समझने के साथ–साथ समय पर सबक लेने की भी बात हो सकती है। क्या हम सब अपने आपको सजग मानकर चल रहे हैं?

राष्ट्रीय सांख्यकीय संगठन(एनएसओ) के आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जनवरी माह में दालों, सब्जियों और मांस–मछली जैसे खाद्य–पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा मंहगाई बढ़ी थी। पिछले बारह महीनों से यह सिलसिला थम नहीं रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मंहगाई की बात तो करने में चूकते नहीं पर, सच्चाई से दूर भागते हैं–यह तथ्य कहने में सकुचाते हैं कि आबादी बढ़ने की गति तेज है। और यह बढ़ती मंहगाई उसी का दुष्परिणाम है। जरा पीछे की ओर जायें, जब 1947 में आजादी मिली थी उस वक्त देश की आबादी मात्र 36 करोड़ के आसपास थी। अब एक अरब तैंतीस करोड़ के आंकड़े को पार करने जा रहे हैं। यह भी न भूलें कि इसमें साढ़े ग्यारह करोड़ घुसपैठिये भी पड़ोसी देशों से नाजायज तरीके से आकर देशभर में फैल चुके हैं। जो अन्य बातों के अलावा देश लिये गम्भीर प्रकार का खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

सन् 2009 में बांग्ला देशियों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। सर्जिकल स्ट्राईक का विरोध बालाकोट के सबूत मांगना, टुकड़े–टुकड़े गैंग को बचाना ये ऐसे तत्वों के सियासी दांव हैं। शाहीनबाग में इकट्ठे हुये ये तत्व पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की मंशा पाले हुये हैं। देश द्रोहियों को समाज से अलग–थलग करके भारत की रक्षा भी करनी होगी। शाहीनबाग में पाकिस्तान जिन्दाबाद 'जिन्ना वाली आजादी' जैसे नारे भी लगे थे। इस साजिश के पीछे भारत में छिपे पाकिस्तानी एजेन्ट, पी.एफ.आई., नक्सली, टुकड़े–टुकड़े गैंग – सब एक ही उद्देश्य से एक जगह इकट्ठे हैं।

लाखों पाकिस्तानी जो सन् 1947 से 2013 तक भारत में वीसा लेकर आये और फिर लौटे ही नहीं। न पाकिस्तान ने पूछा न भारत में उनकी तलाश की गई। ये ही वे तत्व हैं जिनका उपयोग इन नेताओं द्वारा उकसाये जाने पर तोड़–फोड़ करने, करवाने, आग लगाने जैसे कामों में किया जाता है।

अकेले मेरठ में ही ऐसे बीस हजार पाकिस्तानी भूमिगत हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने इन्हें इसी कारण नहीं ढुंढवाया। ऐसा ही पं. बंगाल में मार्कसवादियों ने किया। एक समय था जब ममता बनर्जी घुसपैठियों को रोकने के लिये संसद में गुहार लगाती थी लेकिन अब वोट बैंक की लालच में, इन घुसपैठियों पर उनका प्यार उमड़ रहा है। सन् 2013 में म्याँमार से घुस आये रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू की छावनियों के पीछे

शेष भाग पृष्ठ क्र.4 पर

शाहीनबाग की कुटिलता को जानो - डॉ. किशन कछवाहा

आदमी का जन्म मिला है, तो आदमी जैसे तो रहो। प्रत्येक अपनी इबादत पर चले और दूसरों की आस्था का भी सम्मान करे। तभी देश को दंगों से मुक्त किया जा सकता है। कट्टर अथवा हिंसक व्यक्ति मोहब्बत और शांति की बात नहीं कर सकता। समाज में शांति से रहना है तो सद्भाव की जरूरत है। परस्पर लोगों में नफरत न फैलायी जाय। सब एक दूसरे की इज्जत करें सब धर्मों और पूजा पद्धतियों का सम्मान किया जाय। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाये कि 'हम भड़केंगे नहीं और दूसरे को भड़कायेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, दूसरों को लड़ायेंगे नहीं।'

'शाहीनबाग' जैसे धरना–प्रदर्शन, जे.एन.यू., जामिया मिलिया और जाफराबाद की हिंसक घटनाओं की साम्यता को मो. जिन्ना के 16 अगस्त 1946 की हड़ताल के आव्हान और उसके बाद के परिणामों से तुलना कर आसानी से इस साजिशी योजना के तहत परत–दर–परत बदलते कदमों की आहट को देखा–सुना–समझा जा सकता है। मो. जिन्ना की उस दिन आव्हान की गई हड़ताल और नागरिक संशोधन कानून के विरोध की मानसिकता के साथ साजिश कर्ताओं द्वारा जो खिचड़ी पकाई जा रही थी, आखिर उसका मकसद और क्या हो सकता था कि पूरे देश में आतंक और अस्थिरता का वातावरण निर्मित कर अपनी मनमर्जी थोपे जाने को लेकर मोदी सरकार को बाध्य किया जा सके। इस अघोषित कृत्य में किस किस का सहयोग मिल सकता है–इसकी भी टोह लिया जाना थी । कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का सहयोग मिला भी। वामपंथी और देशविरोधी ताकतें तो कन्धे से कन्धा मिला कर चल ही रही थीं। दिल्ली धधकी तो जरूर, राष्ट्रपति ट्रम्प के आगमन के कारण सरकार के कदम उठे तो पर जरा देर हुयी इसका सुफल यह भी हुआ कि षड़यंत्रकारियों के सारे सूत्र एक एक कर आईने की तरह साफ साफ नजर आ गये।

शाहीनबाग याने क्या? पाकिस्तान बंग्लादेश और अफगानिस्तान इन इस्लामी देशों में अन्याय, अत्याचार और जुल्मों से पीड़ित हिन्दू या सिखों के भारत आने का विरोध करना, हिन्दू मन पर लाऊड स्पीकर, बैनर–पोस्टर के जरिये शब्द–प्रहार किया जाना। इसके साथ ही मुम्बई का वारिस पठान हस माहौल को हवा देने के लिये आग उगल रहा था, वहीं हैदराबाद के औबेसी बंधुओं द्वारा जहर उगला जा रहा था, जे.एन.यू. और जामिया में टुकड़े–टुकड़े गैंग के डॉ. कफील शरजील इमाम जैसे देश घाती तत्व, फिल्मी हस्तियों में गिने जाने वाले कतिपय नासूर भी वैसा कुछ करने में पीछे नहीं थे, जिससे ये आग और भड़के।

इतिहास के पन्ने पलटने से पता चलता है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेता मो. जिन्ना ने भी ऐसी ही आग लगाने की मंशा से एक बड़ी हड़ताल का आव्हान किया था, बाद में उसे 'डायरेक्ट एक्शन' में तब्दील कर भारी मारकाट में बदल दिया था। इसकी भी शुरूआत बड़े–बड़े जुलूसों से हुयी थी 'इसमें भी अल्ला–हो–अकबर, लड़के लैंगे हिन्दुस्तान' जैसे नारे लग रहे थे। विशाल सभा में हिन्दुओं के विनाश की शपथ ली गयी थी, जिहाद की भी घोषणा की गयी थी। दस हजार से अधिक हिन्दुओं का कत्लेआम किया गया था, पन्द्रह हजार के करीब घायल हुये थे, महिलाओं का बलात्कार हुआ था। एक लाख से अधिक बेघरवार हो गये थे। इस हड़ताल के आवाहन का मकसद मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में अलग मुस्लिम प्रान्त की शर्त मनवाना था। यह मांग तो मुस्लिम लीग द्वारा पहले से ही उठाना शुरू कर दी गयी थी लेकिन सन् 1946 आते–आते यह चरम पर थी। मो. जिन्ना का उद्देश्य मुसलमानों के लिये अलग देश बनाना था। हड़ताल के पीछे कुछ और भी उद्देश्य था जिसके लिये पूरी तैयारी की गयी थी, उसके लिये कलकत्ता में भयानक दंगे भड़काये गये। इन दंगों की हवा नोआखाली, पंजाब, बिहार, उड़ीसा तक फैल गयी जिसमें जन–धन की भी भारी हानि हुयी।

यही सब कुछ प्रेरित करने वालों द्वारा 'जिन्नावाली आजादी चाहिये' के नारे शाहीनबाग, जे.एन.यू. और जामिया में भी गूंजे थे। धरना–प्रदर्शन और नारे लगाने वालों के मन में छिपी आकाँक्षा क्या है–इसे इस संदर्भ से समझा जा सकता है।

सन् 1920 में केरल में मोपला–मुसलमानों द्वारा किया गया नरसंहार, सन् 1946 का 'डायरेक्ट एक्शन' के दौरान हुआ हिन्दुओं का कत्लेआम तथा सन् 1947 में आजादी की रात में किया गया सामूहिक रक्तपात– किस तरह की मानसिकता को उजागर करता है– यह सब 'गंगा–जमुनी' तहजीब का सबूत तो नहीं है। मुगल शासन काल में हुयी ज्यादितियाँ नजर अंदाज भी कर दी जायें तो ये अभी की घटनायें हैं। इन तथ्यों को आम लोगों से छिपाने की कोशिशें होती रहीं हैं लेकिन अब साजिश की परतें खुलना शुरू हो गयी हैं।

'भगवा आतंकवाद' का हौआ खड़ा करने वाले कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ''उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'' कहावत चरितार्थ करते रहे तुष्टीकरण तो एक तरफ देश के दुश्मनों को भी संतुष्ट करने से कांग्रेसियों ने परहेज नहीं किया, ऐसी राजनीति देश में चलती रही।

पहले राष्ट्रवादी (तिरंगा झंडा लेकर धरना–प्रदर्शन) फिर पृथकतावादी (देश के टुकड़े टुकड़े होंगे) पहले भीड़, राजनीति के प्रति वितृष्णा रखने वाले संविधान वादी और फिर मजहबी उन्माद को भड़काकर भीड़–हिंसा की सवारी करने वाले मो. जिन्ना के उत्तराधिकारीयों का कौन सा रूप वास्तविक है और कौन सा नकली?

सन् 1947 में भारत का विभाजन हुआ ऐसे ही दबाव में – तत्कालीन भारतीय कमजोर नेतृत्व ने तब भी घुटने टेके थे। परिणाम स्वरूप 13 लाख लोग मारे गये थे, 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर–द्वार–पुश्तैनी व्यवसाय छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा था। 12.5 लाख शरणार्थी भारत आये थे। एक लाख से अधिक महिलाओं का बलात्कार हुआ था– इस काले इतिहास को भारत की जनता से छिपाया गया आजादी मिल गयी, आजादी मिल गयी का राग अलापा गया। बिना खड़ग बिना ढ़ाल – तब क्या लाखों क्रांतिकारियों की शहीदी दास्ताने झूठी है?

भारत विभाजन केवल भूखण्ड का बंटवारा नहीं, यह था हरेक भारतवासी द्वारा लाखों वर्षों से पूजी जा रही भारत माता का खण्डन और लाखों –करोड़ों शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों यशगाथा को मटियामेट किया जाना। कांग्रेस ने अपनी गल्तियों से ब्रिटेन और मो. जिन्ना को अवसर दिया कि वे भारत के टुकड़े–टुकड़े कर सकें।

जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, वह अपना अस्तित्व व पहचान खो बैठता है। पिछले 200 सालों से आक्रमणकारियों का इतिहास भारतीयों को पढ़ाया गया ताकि हिन्दू समाज कमजोर, हीन पराजित मनोबल वाला बना रह सके।

यह प्रश्न भी जेहन में उतारा जाना चाहिये कि जिहादियों द्वारा किये गये हमले की घटनाओं को 'आतंकवाद' कहा जाने का रिवाज बन गया है जबकि खुद

शेष भाग पृष्ठ क्र.4 पर

लाल बाग : शासन बेबस

कश्मीर का लालचौक और बिहार के पटना का लालबाग – ये दोनों स्थान मजहबी उन्मादियों के दुस्साहस के लिये कुख्यात है। ये दोनों मुस्लिम बहुत क्षेत्र हैं, जहां अपराधी बेलगाम है। अपराधी तत्वों द्वारा जब तब गोली और बम चलाना आम बात है। इन तत्वों को स्थानीय नेता और प्रभावशाली लोग सह देते हैं। ये दंगे करते कराते हैं। पुलिस की अपील का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। रैपिड फोर्स की तैनाती ही प्रभावी सिद्ध हो पाती है। इस प्रकार के मुस्लिम बहुल हमेशा संदेह के घेरे में रहते हैं। लालबाग के गुंडे स्थानीय विश्वविद्यालय के छात्रों पर हावी रहते हैं।

मुसलमानों की संतुष्टि के लिये मुसलमानों के लिये लालू राज में अनेक प्रकार के काम कराये गये लेकिन छात्रावास बनने के बाद का माहौल खराब हो गया। इबादत का स्थान बनाया गया था – छात्रों के लिये लेकिन यहां लालबाग के लोग प्रत्येक जुके को नमाज के लिये एकत्रित होते हैं।

पटना में भी साईंस कालेज से लेकर गांधी मैदान के बीच सात मस्जिदें हैं, फिर भी छात्रावास में आकर नमाज पढ़ी जाती है। इसक कारण असामाजिक तत्वों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। छात्र गुंडों का शिकार बनते हैं, छात्राओं पर उनकी गिद्ध दृष्टि रहती है।

प्रशासन के सारे प्रयास विफल रहे हैं। इसी लाल बाग में सी.ए.ए. और एन.आर.सी. को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। सरकार विरोधी नारे लगते हैं। कई बार हिंसक प्रदर्शन हुये । गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी जाती हैं।

सांस्कृतिक मोर्चे पर हम पश्चिम के गुलाम

जितनी चालाकी व छल–प्रपंच से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक–एक कर भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, उससे अधिक चालाकी व छल–प्रपंच से उन्होंने सांस्कृतिक विजय व आंतरिक दोहन की योजना तैयार कर उसे लागू करना आरम्भ किया। भारत और पड़ोसी राज्यों को हड़पने से पहले उनकी कमजोरियों को समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम किया था। इसके साथ राजनीतिक विजय को सांस्कृतिक विजय द्वारा मजबूत करने के लिए उसके समानांतर समस्त ज्ञान संपदा पर अधिकार करके, भारतीय मानस को नियंत्रित करने का जो काम जोंस ने किया, वह आज तक किसी से सम्भव नही हुआ। जिन्हें बर्बाद किया जा रहा था, वे भी कृतज्ञ भाव से वाह वाह कर रहे थे। राजनीतिक पराधीनता से भारत मुक्त हो गया, पर सांस्कृतिक पराधीनता पर गर्व करता है और मुक्त होने की चाह तक नहीं। यह जानते हुए कि सभी अग्रणी देशों का अभ्युदय उनकी अपनी भाओं को शिक्षा, प्रशासन औन अनुसंधान का माध्यम बनाने से हुआ है। जब तक इन सभी क्षेत्रों में विदेशी भाषा का प्रभुत्व है, तब तक कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। अंग्रेजी को गौण भाषा बनाने का विचार तक जोखिम भरा लगता है।

1857 को विद्रोह न हुआ होता तो जो रजवाड़े बचे रह गए थे, वे भी कम्पनी के अधीन होते। विद्राहेह हुआ भी इसलिए कि जोंस की नसीहतों का ध्यान न रखा गया। मीठी छुरी की जगह जहर बुझा खंजर काम में लाया जाने लगा। सांस्कृतिक विजय अभियान में केवल एक बार ही जहर बुझे खंजर से काम लिया गया। यह था, जेम्स मिल द्वारा लिखा गया ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। इस अपवाद को छोड़कर बाद में यदि खंजर चला भी तो सर्जन की छुरी बनकर या जज का हथौड़ा बनकर। इसलिए हम वहा भी वाह–वाह करते रहे, जहां जख्म पर जख्म दिए जा रहे थे। इसी को आत्मपीड़न रति (मैसोकिज्म) कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद का बुद्धिजीवी वर्ग इससे ग्रस्त है। पहले यह व्याधि इतनी उग्र नहीं थी। हमें उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली, स्वतंत्रता नहीं मिली। मानसिक पर निर्भरता से मुक्त हुए बिना कोई व्यक्ति, देश या समाज, स्वतंत्र कैसे हो सकता है? हमारे बुद्धिजीवियों ने अपने समय के मुख्य अंतर्विरोध को समझा ही नहीं। वे उपनिवेश सांचे में बंद होकर सोचने का अभिनय कर रहे थे। यह भी समझ नहीं पाए कि हासिल की गई तो हम नवउपनिवेशवाद के शिकार रहेंगे। उपनिवेशवादी को शांति–व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी, नवउपनिवेशवाद उपद्रव भड़काने पर फलता–फूलता है। पुराना उपनिवेशवाद राजनीतिक आधिपत्य कायम कर पूर्व के औद्योगिक देशों के उद्योग धंधों को नष्ट कर उन्हें बाजार बनाने के लिए कटिबद्ध था। हमारी पीड़ा यह नहीं थी कि राज किसका है, बल्कि यह थी कि इसका धन कहां रहता या जाता है। इसका उत्तर गांधी ने सोचा था और उनसे भी पहले बंगाल के आंदोलनकारियों ने समझा था। औपनिवेशिक आधिपत्य के बाद अंग्रेजों ने सारे उद्योग–धंधों को नष्ट करके अपना बाजार बनाया था। यदि हम अपनी जरूरत की चीजें पैदा करने लगें, बाजार होने से इनकार कर दें तो औपनिवेशिक सत्ता की रीढ़ टूट जाएगी। जल्द से जल्द पश्चिम बनने की नेहरू की लालसा ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम को रोक दिया। कुटीर उद्योग प्रबल आंदोलन नहीं बन सका। कम्युनिष्टों ने राष्ट्रीय पूंजीवादी विकास को बर्बाद कर भारत को नए सिरे से बाजार बना दिया। शासक चले गए, पर उनका आर्थिक साम्राज्य कायम है।

सांस्कृतिक मोर्चे पर आज भी हम पश्चिम के गुलाम हैं। यदि केवल अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त हो जाए तो उनके प्रचारतंत्र की रीढ़ टूट जाएगी। सांस्कृतिक विजय पाए बिना पराधीन रह चुके देश स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमें स्वतंत्रता पाने के लिए नया संघर्ष करना है और जिन्हें संघर्ष करना चाहिए, वे पश्चिम के पिछलग्गू बने हुऐ हैं। जोंस का जादू आज भी काम कर रहा है। इससे बाहर आने की जरूरत है।

बरेली में लटका 270 किलो का झुमका

बरेली को उसका मशहूर झुमका मिल गया। इस झुमके के पीछे बहुत कुछ है। मुंबई के एक डिजाइनर की कल्पना है। पीतल का काम करने वाले मुरादाबादी कारीगर है। बरेली विकास प्राधीकरण का खाली खजाना है। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की दरियादिली है। प्राधिकरण ने इसका सपना तो देखा मगर न बनया न देखरेख की जिम्मेदारी उठा रही है, तो फिर किसका है यह झुमका।

यह झुमका बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का है। उसी ने पैस लगाया। वही इसकी देखभाल भी करेगी। झुमका लगाने का सपना तो बरेली विकास प्राधिकरण(बीडीए)ने देखा लेकिन पूरा करने के लिए सरकारी खजाने की कंगाली सामने आ गई और ध नराशि का इंतजाम नहीं हो पाया। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करीब 20 से 30 लाख रूपए की अनुमानित कीमत का झुमका बरेली–रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लटका दिया गया। हालांकि लागत 40 लाख रूपये खर्च होने की भी चर्चा है।

वहीं, इसके उद्घाटन को लेकर भी काफी विवाद गहरा गया। केन्द्रीय श्रम मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार इसके उद्घाटन में पहुंचे लेकिन मेयर डॉ. उमेश गौतम कार्यक्रम में नजर नहीं आए। उमेश गौतम भाजपा से बरेली के मेयर है। बीडीए बोर्ड में सदस्य राजेश अग्रवाल बताते हैं कि पर्यटन विभाग के विशेष सचिव और पर्यटन विकास निगम के महानिदेशक रह चुके शशांक विक्रम 2015 में बीडीए उपाध्यक्ष बनकर आए तो यह प्रस्ताव उन्होंने बनाया था।

शेष भाग पृष्ठ क्र.1 का

ले जाकर बसा दिया गया है। कौन थे इन्हें यहां पहुंचाने वाले? इसके पीछे वेही लोग थे, जो आज नागरिकता कानून की खिलाफत कर रहे हैं। ये ही इन्हें भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हैं।

अब इस बढ़ती आबादी और उससे बढ़ते खतरों को ज्यादा दिनों तक नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। शाहीनबाग में इकट्ठे हुये लोगों ने अपनी मंशा प्रकट कर दी है कि वे पाकिस्तान की महत्वाकाँक्षा को पूरा करने के लिये क्या–क्या कर सकते हैं? ऐसे तत्वों को भारत के स्वामिमान से खिलवाड़ करने देने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती।

क्या इस तथ्य को नजर अंदाज किया जा सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश बनने के पूर्व) की सेना ने तीन लाख से ज्यादा बंगाली मुसलमानों को कत्ल किया था, बंगाली औरतों का बलात्कार किया था। यह वही पाकिस्तान है जिसकी सेना हर रोज बलूच मुसलमानों का कत्ले आम करती है। यह वही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में भी मुसलमानों का कत्ल कराता है। यह वही पाकिस्तान है जिसके कश्मीर में मुसलमानों को गोली से उड़ाते हैं। शाहीनबाग के सच को समझने और समझाने की जरूरत है।

आज की बढ़ती जनसंख्या भारत की सुरक्षा के लिये शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये अभिशाप बनती जा रही है। सन् 1947 की धार्मिक आधार पर हुये विभाजन के दुष्परिणाम हम सब देख–सुन चुके हैं। वह तत्कालीन राजनीति ही थी जिसने धर्म के आधार पर विभाजन को मजबूर कर दिया था। इसी धार्मिक भेदभाव के कारण ही कश्मीर अपने घर से ही 5 लाख से अधिक कश्मीरियों को बलात् घर–द्वार–व्यापार, पुस्तैनी जमीन–जायदाद छोड़कर चले जाने को बाध्य कर दिया गया था। इसे 'जनसंख्या जिहाद' कहा गया था। यह बढ़ती हुयी जनसंख्या विद्यमान संसाधनों को खा रही है। वहीं औद्योगिकरण होने से प्रदूषण, बढ़ती आवश्यक वस्तुओं की मांग पूरी करने मिलावट की जा रही है। कुपोषण, भयंकर बीमारियाँ, अतिकमण–लूटमार, हिंसा नक्सलवाद, आतंकवाद आदि मानवीय आपदाओं के कारण निरन्तर स्थितियाँ विस्फोटक बन रहीं हैं।

शेष भाग पृष्ठ क्र.2 का

हमला करने वाले अपने इस दुष्कृत्य को युद्ध 'होलीवार' कहने–मानने से अलग नहीं है। एक गलती को दूसरी गलती की ओर जे जाने का प्रयास है। जिस मजहबी 'इस्लाम' में मुसलमानों की इतनी श्रद्धा–विश्वास है, उसमें ऐसा क्या है–जो सब जगह इतनी बड़ी संख्या में हिंसक प्रवृत्तियों को पैदा कर रही है। दुर्भाग्य से इस प्रकार विचार अब तक क्यों नहीं हुआ?

पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जनाजे में तो पचास मुसलमान शामिल नहीं हुये, दूसरी तरफ आतंकियों के जनाजे में लाखों की संख्या में मुसलमान शामिल होते हैं। और इतना ही नहीं उनके जनाजे और दफनाने की रस्में भी आयोजित की जाती है।

सन् 1971 में जब पाकिस्तान की फौज वर्तमान बंगलादेश में घुसी थी तब भी निशान लगाकर हिन्दुओं के घरों को निशाना बनाया गया था, लाखों की संख्या में नरसंहार हुआ था विश्व में भारत ही एक ऐसा अजीब देश है, जहां पीड़ा, वेदना भरे अत्याचारों को जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता और इस बात को महत्व दिया जाता है कि वह उस पीड़ा को और अपने पूर्व कालीन गौरव की स्मृतियों को मिटा कर आगे बढ़ें।

आश्चर्य और दुःख तो इस बात का है कि इतने बड़े हृदय द्रावक हादसे और अत्याचार, जुल्मों–सितम के दौर एक बार नहीं अनेकानेक बार चलते रहे लेकिन किसी भी नेता, साहित्यकार, लेखक ने इनका उल्लेख करने का साहस न तो दिखाया न ही इन दुर्भाग्य जनक परिस्थितियों में मार डाले गये इंसानों को लेकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किये, न ही एक मोमबत्ती जलाकर सहानुभूमि व्यक्त की गई। उल्टे दबाये, कुचले और प्रताड़ितों की स्मृति ही मिटा देने के कुत्सित प्रयास हुये।

अब इस श्राद्ध और तर्पण करने वाले हिन्दू समाज को यह भी स्मरण रखना होगा कि यदि हम आज जीवित हैं तो अपने पूर्वजों की उस बलिदानी परम्परा के कारण जो धर्म और समाज के लिये समर्पित थे। नयी पीढ़ी अब जाग चुकी है, जो बीत गया उसे भुला दो' के पक्ष में नहीं है। उसका धैर्य टूट चुका है। उसे घात और प्रतिघात समझ में आने लगा है।

पंजीकृत समाचार पत्र सम्बंधी
घोषणा पत्र
फार्म–4(नियम–8)

महाकोशल संदेश(साप्ताहिक)(RNI NO. MPHIN 2001/11140)

प्रकाशन स्थाल	–	विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं.1, म.नं.1692, नव आदर्श कालोनी गढ़ा मार्ग, जबलपुर(म.प्र.)
मुद्रक का नाम	–	विश्व संवाद केन्द्र द्वारा अधिकृत श्री दीपक गुप्ता
पता	–	ओम ऑफसेट प्रिंटर्स, 239 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, बल्देवबाग चौक, जबलपुर.
प्रकाशक	–	डॉ. किशन कछवाहा
राष्ट्रीयता	–	भारतीय
पता	–	विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं.1, म. नं. 1692, नव आदर्श कालोनी, गढ़ा मार्ग, जबलपुर(म.प्र.)
सम्पादक	–	डॉ. किशन कछवाहा
राष्ट्रीयता	–	भारतीय
पता	–	विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं.1, म. नं. 1692, नव आदर्श कालोनी, गढ़ा मार्ग, जबलपुर(म.प्र.)

मैं डॉ. किशन कछवाहा एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

अपठित हस्ताक्षर

मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में हिन्दू विश्वविद्यालय

इंडोनेशिया में रामचरित मानस के एक पात्र सुग्रीव के नाम पर पहला हिन्दू विश्वविद्यालय खोला गया है। इंडोनेशिया ने राजधानी बाली के देनपासर के हिंदू धर्म इंस्टीट्यूट को प्रेजीडेंशियल रेगुलेशन के तहत देश की पहली हिंदू स्टेट यूनिवर्सिटी बना दिया है।

इस विश्वविद्यालय का नाम ''आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू युनिवर्सिटी'' रखा गया है। यह रेगुलेशन दो सप्ताह पहले ही लागू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है लेकिन इसकी संस्कृति में रामायण रची बसी है। इस नए प्रेजीडेंशियल रेगुलेशन का उद्देश्य हिंदू उच्च शिक्षा का बढ़ावा देना है।

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

– सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com